"दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का अधिकार"

अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों:

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जो भारत द्वारा पुष्टि की गई है, मैं कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार समावेशी शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे भारत ने अपनाया है, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करता है, जिन्हें एसडीजी लक्ष्य 4 को आगे बढ़ाने मे लक्षित कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जो सभी की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में 'समावेशी गुणवत्ता और समान शिक्षा' की पुष्टि करता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) शिक्षण, संस्कृतियों और समुदायों में बढती भागीदारी के माध्यम से शिक्षार्थियों की जरूरतों की विविधता को संबंधित करने और प्रतिक्रिया करने और शिक्षा के भीतर और बाहर करने को कम करने की प्रकिया के रूप में समावेशी शिक्षा को देखता है। इसमें एक सामान्य दृष्टि के साथ सामग्री, दृष्टि के साथ सामग्री, दृष्टिकोण, संरचना और प्रतीक है कि सभी बच्चों को शिक्षित करना मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है।

संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय के मानवधिकार के लिए रिपोर्ट (OHCHR) शिक्षा पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर 2013 के अध्ययन पर (2013) मानवधिकार परिषद के पच्चीसवें सत्र में 2014 में प्रस्तुत समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार का एहसास करने साधन के रूप में।

समावेशी शिक्षा पर अधिकार के साथ व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति सामान्य टिप्पणी नंबर 4 (2016) समावेशी शिक्षा का अधिकार जो उन राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिन्होंने सम्मेलन की पुष्टि की है, समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय दायित्वों:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2016 और शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या दिव्यांगों की असमानताओं से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की विविधताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को तैयार करने और मजबूत करने के महत्व पर बल देता है। इसलिए, दिव्यांग बच्चों को बनाए रखने के लिए, स्कूलों को बच्चे द्वारा आवश्यक सहायता सेवाओं, प्रशिक्षित/संवेदी शिक्षक की उपलब्धता, संसाधन शिक्षक से सहायता, साथियों द्वारा स्वीकृति और समावेशी शिक्षण प्रथाओं के संदर्भ में तैयार किया जाना आवश्यक है।

सर्वशिक्षा अभियान एसएसए यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग से पीड़ित हर तरह की, श्रेणी और डिग्री की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण, विकल्पों और रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय के मानवधिकार के लिए रिपोर्ट (OHCHR) शिक्षा पर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर 2013 के अध्ययन पर (2013) मानवधिकार परिषद के पच्चीसवें सत्र में 2014 में प्रस्तुत समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है दिव्यांग व्याक्यिों के लिए शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार का एहसास करने के साधन के रूप में।

समावेशी शिक्षा पर अधिकार के साथ व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति सामान्य टिप्पणी नंबर 4 (2016) समावेशी शिक्षा का अधिकार जो उन राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिन्होंने सम्मेलन की पुष्टि की है, समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय दायित्वों:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या दिव्यांगों की असमानताओं से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की विविधताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को तैयार करने और मजबूत करने के महत्व पर बल देता है। इसलिए, दिव्यांग बच्चों को बनाए रखने के लिए, स्कूलों को बच्चे द्वारा आवश्वयक सहायता सेवाओं, प्रतिशक्षित/संवेदी शिक्षक की उपलब्धता, संसाधन शिक्षक से सहायता, साथियों द्वारा स्वीकृति और समावेशी शिक्षण प्रथाओं के संदर्भ में तैयार किया जाना आवश्यक है।

सर्वशिक्षा अभियान एसएसए यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग से पीड़ित हर तरह की, श्रेणी और डिग्री की परवाह किए बिना, गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण, विकल्पों और रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन किया जाए।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 17 में राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है;

A. दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए हर पांच साल में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने के लिए, उनकी विशेष जरूरतों का पता लगाने और इनमें मिलने की हद तक: बशर्ते इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पहला सर्वेक्षण किया जाएगा;
B. पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना;
C. दिव्यांगता वाले शिक्षकों सहित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और नियोजित करने के लिए, जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में योग्य हैं और ऐसे शिक्षक भी हैं जो बौद्धक दिव्यांगता वाले बच्चों को पढ़ाने में प्रशिक्षित हैं;
D. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए पेशेवरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना

E. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों का समर्थन के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधन केंद्र स्थापित करना;

F. संचार के साधनों और स्वरूपों सहित उपयुक्त संवर्द्धन और वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भाषण, संचार या भाषा दिव्यांग व्यक्तियों की दैनिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं के भाषण के उपयोग को पूरक करने के लिए और उन्हें सक्षम बनाता है। भाग लेने और उनके समुदाय और समाज में योगदान करने के लिए;

G. किताबें, अन्य शिक्षण सामग्री और आठ साल की उम्र तक की बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए;

H. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों का उचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए;

I. दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने के लिए जैसे कि परीक्षा के पेपर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, मुंशी की सुविधा या सुविधा या एमन्यूनिसिस, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट;

J. सीखने बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना; और

K. कोई अन्य उपाय, जैसा भी आवश्यक हो

इसके अलावा, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, (एनपीएसी) 2016 भी दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट संदर्भ बनाता है। इसमें कहा गया है, '' आरटीई अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए पार्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे के साथ प्राथमिक स्कूलों तक पहुँच सुनिश्चित करें।'' इसके भीतर सभी दिव्यांग बच्चों को बिना भेदभाव के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कड़े तंत्र स्थापित करने की बात करता है और दिव्यांग छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और नियमित स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने के बारे में शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के बीच क्षमता और जागरूकता विकसित करना और यह सुनिश्चित करना कि ये समावेशी हैं।

इस अभ्यावेदन के माध्यम से हम आपसे राज्य शिक्षा विभाग से जुड़ने का अनुरोध करते हैं ताकि राज्य मे निजी मुख्यधारा के स्कूलों सहित सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को वास्तविकता बनाया जा सके।

डॉ0 शिवाजी कुमार
दिव्यांग विशेषज्ञ